

Unit of Application—With regard to the unit of application of ceiling, namely, whether ceiling should be applicable to lands held by each individual land-holder or to the aggregate area of land held by all the members in a family, it was decided that the manner of fixing ceiling on family basis should be decided after detailed information has been received about the working of the provisions in the existing legislation in the various States

Exemptions—It was agreed that the exemptions from ceiling should be curtailed to the minimum in the light of the local conditions

However by a recent amendment the level of ceiling has been reduced in West Bengal by President's enactment from 25 acres to 12.4 acres (5 hectares) in irrigated areas and 17.3 (7 hectares) in case of other areas and it has been made applicable to aggregate area of land own by all rayats in a family. Allowance is made for size of the family subject to an overall ceiling of 24.2 acres (9.8 hectares). In Assam, the ceiling limit has been reduced from 50 to 25 acres. In Kerala where the level of ceiling had been reduced earlier, Land Reforms Act has been amended to facilitate expeditious determination of compensation by de-linking it from market value and fixing it at a flat rate depending upon class of land

पेंशन बीमा योजना

*419. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी :
श्री लाल आडवाणी :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य निधि अधिनियम में हाल ही में किये गये सशोधन के फलस्वरूप कितने कर्मचारियों को पेंशन बीमा योजना द्वारा लाभ पहुंचेगा, और

(ख) कितने कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे और इन लोगों को भी लाभ पहुंचाने के लिये सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

‡ [PENSION INSURANCE SCHEME

419 SHRI SUNDAR SINGH ·
BHANDARI

SHRI LAL K ADVANI.

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION/श्रम और पुनर्वास मंत्री be pleased to state

(a) the number of employees likely to be benefited by the Pension Insurance Scheme provided by a recent amendment in the Provident Fund Act, and

(b) the number of employees who will not be able to avail themselves of the benefit of the scheme and the details of the scheme worked out by Government for benefiting them also ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री

(श्री बालगोविन्द वर्मा) परिवार पेंशन व जीवन बीमा योजना की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यायी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है —

(क) परिवार पेंशन व जीवन बीमा योजना 1971 ऐसे सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जो 1-3-1971 को या उसके बाद साविधिक भविष्य निधि या छूट प्राप्त भविष्य निधि के सदस्य बनते हैं। जो कर्मचारी उक्त तारीख को इन दोनों निधियों में से किसी एक निधि के पहले से ही सदस्य हैं, उन्हें इस योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। चूंकि विकल्प देने की अंतिम तारीख 31 अगस्त, 1971 है, अतएव इतनी जल्दी युक्त यथार्थता से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता कि नई योजना से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी।

(ख) तथापि, ऐसे सदस्य, जो परिवार पेंशन व जीवन बीमा योजना में शामिल

होने का विकल्प नहीं देने, वर्तमान शर्तों के अनुसार भविष्य निधि का पूर्ण लाभ प्राप्त करते रहेंगे और वे इस योजना के सदस्यों की भांति अपने अशदानों के किसी भाग को नई योजना की ओर अपवर्तित नहीं कराएंगे।

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION/ श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय में उप मंत्री (SHRI BALGOVIND VERMA): The administration of the Family Pension-cum-Life Assurance Scheme is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and not the direct concern of the Central Government. The Provident Fund authorities have intimated as under:—

(a) The family pension-cum-life assurance scheme, 1971 covers all employees who become members of the statutory Provident Fund or an exempted provident fund on and after 1-3-1971. The employees who are already members of either of the funds on the said date have been given an option to join this Scheme. Since the last date for the exercise of options is 31st August, 1971 it is too early to forecast with reasonable accuracy the number of employees who would be benefited by the new scheme.

(b) Such of the members who do not opt to join the family pension-cum-life assurance scheme would, however, continue to get the full benefit of provident fund under existing terms and will not have any part of their contributions diverted to the new scheme as in the case of the members of that scheme.]

खनिज भण्डारों का व्यापक सर्वेक्षण

* 420. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश के खनिज भण्डारों की विशालता को देखते हुये इनका कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है यदि हा, तो उम्मा ब्यौरा क्या है

(ख) क्या यह सच है कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल के खनिज भण्डारों के सबध में विभाग द्वारा मातिला व्यवहार प्रदर्शित किया जा रहा है,

(ग) क्या यह सच है कि विभाग द्वारा गठित दर्जनो समितियों, बोर्डों तथा उप-समितियों में विभागीय लोगों की भरमार है और सम्बद्ध राज्यों के लोक प्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई है , और

(घ) यदि हा, तो क्या सरकार इन निकायों की सदस्य सूची की जाच करायेंगी?

[COMPREHENSIVE SURVEY OF MINERAL DEPOSITS

420 SHRI J P YADAV : Will the Minister of STEEL AND MINES/ इस्पात और खान मंत्री be pleased to state .

(a) whether a comprehensive survey has been made in view of the vastness of the mineral deposits of the country, if so, what are the details thereof,

(b) whether it is a fact that in the matter of mineral deposits of Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bengal, a step montherly treatment is being shown by the Department;

(c) whether it is a fact that the dozens of Committees, Boards, sub-committees constituted by the Department are dominated by the departmental people and the public representatives of the concerned States have been neglected; and

(d) if so, whether Government would enquire into the panels of members of these bodies ?]

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) (क) से (घ) विवरण मभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 1851 में अपने प्रारम्भण में ही देश में खनिज निक्षेपों के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण करने आ रहा है और उसके परिणामस्वरूप विभिन्न खनिजों